कोविड-19 एवं अर्थव्यवस्था: संकट और चुनौतियाँ

डॉ. लखन चौधरी*

कल्याण स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

कोविड–19 वैश्विक महामारी, संकट एवं त्रासदी को लेकर इस समय पूरी दुनिया में अफरातफरी, दहशत एवं खलभली मची हुई है। जहां एक तरफ दुनिया के सामने लोगों की जिंदगी बचाने की चिंता है, वहीं दूसरी ओर कारोबार, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–धंधे एवं अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की चिंता भी बरकरार है। लोगों की जान बचाने और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भारत सहित दुनियाभर के सैकड़ों विकसित एवं विकासशील देशों ने अपने–अपने हिसाब से पिछले साल कई सप्ताह–महिने तक के लिए अपने–अपने देश में 'लॉकडाउन' किया है, और अब फिर से वही दौर शुरू हो चुका है। पिछले अनुभवों के आधार पर इससे वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने में बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कारोबार, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग–धंधों सहित लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों के लंबे समय तक बंद रहने से दुनियाभर की विकसित एवं विकासशील सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में हताशा, निराशा, सुस्ती एवं मंदी छाई हुई है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में कारोबार, व्यापार–व्यवसाय, उत्पादन ठप होने के कारण व्यापक पैमाने पर नौकरियों से छंटनी के कारण बेरोजगारी दर में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही में भारत में बेरोजगारी दर 23–25 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, और विकासदर 24 प्रतिशत तक के ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गया था। कारखाने, उद्योग–धंधे एवं औद्योगिक उत्पादन सहित सभी आर्थिक–कारोबारी गतिविधियां लंबे समय तक बंद होने के कारण श्रमिकों, कामगारों का भारी मात्रा में पलायन हुआ। प्रवासी श्रमिकों के पलायन या घर वापसी के कारण देश–दुनिया में कोहराम मचा। इससे जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ वायरस का संक्रमण फैला।

इस वैश्विक महामारी एवं त्रासदी से उबरने और निकलने के लिए दुनियाभर में अपने–अपने तरीके से सर्वाधिक और सर्वोत्तम प्रबल प्रयास एवं उत्कृट उपक्रम जोरों से हुए एवं हो रहे हैं। अभी सबकी चिंताएं केवल इतनी है कि कैसे भी इस संकट से उबरा जाए, कैसे भी करके इस महामारी से लोगों को बचाया जाए। लेकिन अब सरकारों के साथ जनमानस को भी यह चिंता सताने लगी है कि कोविड–19 संकट के बाद क्या होगा ? देश–दुनिया में क्या–कुछ बदलेगा? कितना बदलेगा? लोग कितने बदलेंगे ? लोगों की जीवनचर्या या जीवनशैली कितनी बदलेगी? खान–पान, रहन–सहन के तौर–तरीके कितने और किस तरह बदलेंगे? इस बीच सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम से देश के सार्वजनिक क्षेत्रों का तेजी के साथ निजीकरण करने में लगी हुई है। जबकि इस समय देश की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती एवं मंदी को दूर करने के उपाय एवं समाधान के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को साथ लेकर ही चलने की जरूरत है, जैसे कि अभी तक देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ चलकर विकास किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भष्ट्राचार, लालफीताशाही, नौकरशाही, अफसरशाही, भाई–भतीजावाद, फिजूलखर्ची को रोकने और इस पर कठोर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है।

इधर हमारे सरकारी तंत्र की खामियों एवं नाकामियों ने देश के करोड़ों प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को सड़कों पर बेबस छोड़कर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के साथ दोहरा अन्याय किया। एक तो उन्हें लॉकडाउन कालखण्ड का वेतन नहीं दिया जिसके कारण वे मजबूरन घर लौटने को विवश हुए, दूसरी तरफ सरकार उन्हें सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने में नाकाम रही। उपर से काम के घंटे बढ़ाने वाले श्रम कानून में रातोंरात बदलाव करते हुए मजदूरों पर एक और कुठाराघात किया गया। चार घंटे प्रतिदिन काम के घंटे बढ़ाने संबंधी श्रम कानून में रातों–रात बदलाव एवं परिवर्तन कर दिया गया है। इस नये श्रम कानून के अनुसार अब प्रतिदिन 8 घंटे के स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे और प्रति सप्ताह 72 घंटे की कार्यअवधि लागू करने की बात है।

*Corresponding Author: Email: lakhanchoudhary3@ gmail.com • Mobile No. 9406050407

कोरोना के कई कारणों की पड़ताल से एक बात साफ है कि धरती, प्रकृति अब हमारी 8 अरब आबादी के बोझ को सहन नहीं कर पा रही है, इस कारण वह संतुलनकारी उपाय कर रही है। कोविड–19 प्रकृति के संतुलनकारी नीति का ही परिणाम है, जिसकी घोशणा ब्रिटिश पादरी एवं प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माल्थस ने आज से सवा दो सौ साल पहले ही कर दी थी। इसके बावजूद हमारी सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम सामने है। तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं इस समस्या की जड़ में धरती पर बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या की कार्य गतिविधियां हैं। इसलिए अब लोगों को अपनी जीवनशैली में बदलाव एवं परिवर्तन करना होगा। खान–पान, रहन–सहन के तौर–तरीके बदलने होंगे। सामाजिक दूरियां या सही मायने में कहा जाये भौतिक दूरियां को अब जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने, बार–बार हाथ धोने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। बुनियादी साफ–सफाई एवं सुरक्षात्मक उपायों के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब यह सोचना होगा कि जीवन, प्रकृति, यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, इन पर हमारी आगामी पीढ़ियों का भी अधिकार है। तभी यह दुनिया, यह जीवन आबाद रहेंगे। चूंकि आज से ठीक सौ साल पहले 1918–20 में भी इस दुनिया में इस तरह के खतरे आ चुके हैं, और भविष्य में भी इस तरह की आपदाएं आती रहेंगी, इसलिए सावधानी, सतर्कता और आवश्यक भौतिक एवं सामाजिक दूरियां बनाकर रहना आवश्यक एवं अनिवार्य है।

प्रस्तावना

कोविड–19 को लेकर पूरी दुनिया अभी भी संकट और दुविधा के दौर से गुजर रही है। इस वैश्विक महामारी एवं त्रासदी से उबरने और निकलने के लिए दुनियाभर में अपने–अपने तरीके से सर्वाधिक और सर्वोत्तम प्रबल प्रयास एवं उत्कृट उपक्रम जोरों से हो रहे है। अभी सबकी चिंताएं केवल इतनी है कि कैसे भी इस संकट से उबरा जाए, कैसे भी करके इस महामारी से लोगों को बचाया जाए। लेकिन अब सरकारों के साथ जनमानस को भी यह चिंता सताने लगी है कि कोविड–19 संकट के बाद क्या होगा? देश–दुनिया में क्या–कुछ बदलेगा? कितना बदलेगा? लोग कितने बदलेंगे? लोगों की जीवनचर्या या जीवनशैली कितनी बदलेगी? खान–पान, रहन–सहन के तरीके कितने और किस तरह बदलेंगे? क्या सोचने, जीवन जीने का तरीका भी बदल सकता है? क्या दुनिया इस महामारी एवं त्रासदी से उबरकर और निकलकर फिर से पूर्ववत हो पायेगी ? यह भी एक बड़ा सवाल है।

इस बीच यह सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या कोविड–19 संकट के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग इसी तरह हमेशा बना कर रहना होगा ? कब तक लोग–बाग घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाकर रहेंगे या मुंह छुपाकर जियेंगे? कब तक बार–बार हाथ धोने एवं धोते रहने तथा उसके बाद सेनेटाइजर लगाने का कार्यक्रम एवं कारोबार चलेगा? इस तरह की सामाजिक दूरियां और मनोवैज्ञानिक मजबूरियां कब तक चलेंगी? आमजन की जिंदगी कब पटरी पर रेल की तरह सरपट दौड़ेगी? कब परिस्थितियां सामान्य होंगी? आम आदमी का जनजीवन कब सामान्य हो सकेगा? कितनों दिनों के बाद और कितनों दिनों तक के लिए? धरती पर इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां कब तक आती रहेंगी? तथा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इन सब घटनाओं से मनुष्य, मनुष्य जाति सीख एवं सबक लेगा, सीखेगा? क्या आपने सोचा है क्या होगा, कैसे बदलेगा जीवन? क्या–क्या बदल सकता है कोविड–19 संकट अथवा कोरोना की इस वैश्विक महामारी से? याद रखिए जीवन में हर त्रासदी और महामारी के बाद पुरानी मान्यताएं ओर धारणाएं टूटती हैं, और नई–नई आर्थिक सिद्धांतों एवं विचारों की पोल खोलकर रख दी थी, ऐसे में विकल्प के तौर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स की नई आर्थिक विचारधारा को व्यापक समर्थन मिला और दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे अपनाना शुरू किया था।

कीन्स के अनुसार 'कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी सुधार या मरम्मत स्वयं नहीं कर सकती या कहें कि मंदी की स्थिति में स्वयं ऊपर नहीं उठ सकती। अर्थव्यवस्था को सुस्ती एवं मंदी से उबारने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत होती है और ये बड़े सुधार केवल सरकार ही कर सकती है।' इसके लिए कीन्स ने मंदी में तबाह हुई अर्थव्यवस्था में कुल–मांग (Agrregate Demand) जिसे उन्होनें 'प्रभावपूर्ण मांग' (Effective Demand) कहा, को बढ़ाने पर जोर देने की बात कही थी। चूंकि मंदी काल में अर्थव्यवस्था में व्यापक बेरोजगारी के कारण समाज की क्रय–शक्ति (Purchashing Power) क्षीण हो जाती है, तथा बढ़ते घाटे और पूंजी बाजार में अविश्वास के कारण निजी निवेश (Private Investment) लगभग बंद हो जाते है इसलिए अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र में सालों–साल फंसी रह जाती है। मंदी के दुष्चक्र से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत होती है, और बाजार में कुल–मांग/प्रभावपूर्ण मांग (Agrregate Demand/ Effective Demand) पैदा करनी होती है।

इसके लिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती है। सरकार नई–नई सामाजिक–आर्थिक नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से सरकारी खर्च में वृद्धि करते हुए लोगों को काम देकर उनकी आमदनी बढ़ाकर क्रय–शक्ति बढ़ाते हुए बाजार में तरलता एवं मांग उत्पन्न कर सकती है या सरकार को करनी चाहिए। समाज के निम्न आय समूहों (Low Income Groups) को सीधे आर्थिक सहायता (Cash) देकर लोगों में नकदी हस्तांतरण के द्वारा बाजार में मांग बढ़ाकर तात्कालिक मंदी को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार लोगों की नौकरियों को बचाए बल्कि नौकरियों के और नये–नये अवसर पैदा करे। औद्योगिक और वित्तीय इकाइयों के लिए बड़े आर्थिक पैकेज लेकर आए, जिससे औद्योगिक तालाबंदी को रोका जा सके। इसका सम्मिलित प्रभाव सीधे

तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में होता है। पुर्णबंदी (Lockdown) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक ढांचा असंतुलित हो गया है। इस अप्रत्याशित घटना या आपदा से देश के आर्थिक हालात चरमरा गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति 1930 की दशक के मंदी की तरह हो गई है। देश एवं विदेश के अनेक अर्थशास्त्रियों सहित अनेक आर्थिक संस्थाओं एवं संगठनों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों की ओर इशारा किया है।

अर्थव्यवस्था के लिए तमाम रेटिंग एजेंसियां और अब तो आरबीआई तक ने अपने रिपोर्ट में विकासदर के (GDP Growth Rate) नकारात्मक रहने की बात कही है। देश में बेरोजगारी दर पहले से ही पिछले 45 सालों के सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है, और अभी देश में बेरोजगारी दर 08–10 प्रतिशत के आस–पास बनी हुई है। देश में 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी दर 21–22 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग एक–तिहाई के आस–पास जा चुकी है। अभी खबरें आ रही हैं कि पिछले एक साल के कोविड कालखण्ड में भारत में गरीबों की संख्या साढ़े सात करोड़ बढ़ी है। इस समय देश में कुल कार्यशील जनसंख्या (कुल आयु कार्यशील जनसंख्या 15–64 वर्ष), कुल जनसंख्या का लगभग 63–65 प्रतिशत है, यानि देश की 87–90 करोड़ जनसंख्या और कहा जा रहा है कि इसमें से लगभग एक–तिहाई कार्यशील जनसंख्या अपना रोजगार खो चुकी है। सरकारी अनुमान के अनुसार भी विकासदर आगामी सालों में नकारात्मक हो सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर महामंदी की स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

PSUs की उपेक्षा और निगमीकरण के रास्ते पर देश

अब भारतीय अर्थव्यवस्था निजीकरण से एक कदम आगे बढ़ते हुए निगमीकरण के रास्ते पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। देश के करोड़ों गांवों, देहातों, किसानों, श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, निर्धनों को निजीकरण एवं निगमीकरण के रास्ते पर रोजी–रोटी, रोजगार एवं उनके आजीविका के साधन उपलब्ध कराने को लेकर सरकार काम कर रही है। सरकार के पिछले दिनों के फैसलों को देखने से यही लग रहा है, कि अब देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की अधिक उपयोगिता नहीं रह गई है। स्वतंत्रता के बाद 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' की महत्वपूर्ण नीतियों के तहत एक समाजवादी लोक–कल्याणकारी राज्य की संकल्पनाओं को साकार करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित एवं विकसित की गई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (PSUs) की, भाायद अब देश को अधिक जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए सरकार लगातार इनके विनिवेश के निर्णय को सरपट आगे बढ़ाते जा रही है।

वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सरकार का निजीकरण का फैसला इसलिए अनुचित, अनुपयोगी एवं अहितकारी है, क्योंकि भारत में आज भी एक–तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवननिर्वाह करती है। सरकार के ही विभिन्न एजेंसियों एवं संस्थाओं के अनुसार देश की दो–तिहाई ग्रामीण आबादी का प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जीवननिर्वाह खर्च 50 रूपए से कम और एक–तिहाई शहरी आबादी का प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जीवननिर्वाह खर्च 100 रूपए से कम है। ऐसे हालात में सरकार का यह निर्णय देशहित में कैसे कहा जा सकता है?

शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजीकरण को प्रोत्साहन और बढ़ावा से देश को क्या हासिल हुआ ? आज कारोना संकट कालखण्ड में देशहित में कौन सा निजी क्षेत्र काम कर रहा है ? कृषि जमीनों का अधिग्रहण करके 'सेज' बनाने से कितने किसानों को फायदा हुआ है? कृषि में निजी कंपनियों को बीज, बीमा, कृषि–उपकरण आपूर्ति का ठेका देने से कितने किसानों का कितना भला हुआ और हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अभी निजी क्षेत्र की कितने कंपनियों और औद्योगिक कारखानों एवं घरानों ने प्रवारी मजदूरों को लॉकडाउन कालखण्ड का वेतन भुगतान किया है? क्यों करोड़ों अंतरराज्जीय प्रवासी मजदूर इस तरह बदहवास अपने घर की ओर भाग रहे हैं? कितने सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का लॉकडाउन कालखण्ड का वेतन कटा? इन सवालों को सरकार से पूछने की जरूरत है। अपने आप समझ आ जायेगा कि निजीकरण एवं निगमीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र में क्या फर्क है।

इस समय देश की अर्थव्यवस्था के समाधान के लिए सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, जैसे कि अभी तक देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ चलकर विकास किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भष्ट्राचार, लालफीताशाही, नौकरशाही, अफसरशाही, भाई–भतीजावाद, फिजूलखर्ची को रोकने, इस पर नियंत्रण लगाने के बजाए उसका निजीकरण एवं निगमीकरण करना बेहद निरर्थक एवं खतरनाक कदम है। इन कदमों एवं उपायों पर सरकार यदि नियंत्रण कर लेती है तो देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा। कोयला–लौहअयस्क जैसे प्राकृतिक संपदा, साधन एवं संसाधन, रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा, बीमा, बैंकिग, सड़क, रेलपरिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, अंतरिक्ष–परमाणु विकास जैसे अतिसंवेदनशील एवं जनसरोकारी क्षेत्रों को निजी एवं कार्पोरेट क्षेत्रों को सौंपना भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।

इस समय कृषि क्षेत्र के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संभालने एवं पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र अकेले 27–30 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। एमएसएमई जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कहा जाता है, लगभग 13–15 करोड़ लोगों

को रोजगार देता है। मतलब इन दोनों क्षेत्रों में 40–45 करोड़ लोग अपनी आजीविका एवं जीवननिर्वाह के लिए निर्भर हैं। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को सबसे पहले मजबूत करने की आवश्यकता है। आज दश के 8–10 करोड़ अंतरराज्जीय अप्रवासी श्रमिक केवल इसी क्षेत्र में खप सकते हैं। इसके लिए कृषि एवं एमएसएमई के आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने की जरूरत है।

कोविड–19 के संदर्भ में माल्थस की प्रासंगिकता

कोविड–19 आज पूरी मानवता के लिए खतरा बन गई है। आज पूरी दुनिया एक बार फिर एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी से जुझने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस समय इस महामारी की मुख्य जड़ के बारे कोई चर्चा या परिचर्चा नहीं हो रही है। दरअसल में इसकी मुख्य वजह धरती में बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, और इसके कारण प्रकृति का अंधाधुंध दुरूपयोग है। धरती, प्रकृति इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है, इस कारण वह संतुलनकारी उपाय कर रही है। कोविड–19 प्रकृति के संतुलनकारी नीति का ही परिणाम है, जिसकी घोषणा ब्रिटिश पादरी एवं प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माल्थस ने आज से सवा दो सौ साल पहले ही कर दी थी। इसके बावजूद हमारी सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम सामने है।

आज से सवा दो सौ साल पहले माल्थस ने जनसंख्या को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह एकदम सही एवं सटीक साबित हो रही है। माल्थस के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव की स्थिति में भूखमरी, बीमारी, महामारी, युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि और अन्य तरह–तरह की प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियां उत्पन्न होने के कारण जनसंख्या में मृत्यु के द्वारा कमी आती है, अर्थात जनसंख्या नियन्त्रित हो जाती है, और पहली अवस्था में वापस आ जाती है। जनसंख्या नियन्त्रण के इन कारणों को थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने "सकारात्मक उपाय" कहा। माल्थस ने विवाह नहीं करना, देरी से विवाह, ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, विवाह के बाद भी आत्म संयम जैसे नैतिक "निवारक उपायों" की भी बात कही है, जिनके असफल होने की स्थिति में इस प्रकार की महामारियां एवं प्राकृतिक आपदाएं आना अवश्यंभावी है।

माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या की वृद्धि दर गुणोत्तर श्रेणी या ज्यामितीय दर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न इत्यादि जीविकोपार्जन के साधन समानान्तर श्रेणी या अंकगणितीय दर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि का यह असंतुलन इतना अधिक हो जाता है कि 25 वर्ष में किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। 200 वर्षों में जनसंख्या एवं साधन–संसाधन का अनुपात 256 : 9 हो जाता है। यही असंतुलन धीरे–धीरे संकट का कारण बनता है, जैसे आज कोविड–19 दुनिया के लिए संकट बन चुकी है। माल्थस के बातों से दुनिया अनभिज्ञ है, ऐसी बात नहीं है। माल्थस की चेतावनी सभी भली–भांति जानते हैं लेकिन जब अमल की बात है तब सभी सरकारें चुप हो जाते हैं।

आज दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रतिदिन 3.95 लाख बच्चे जन्म ले रहे है, जिसमें से 1.53 लाख की मृत्यु हो जा रही है, और इस प्रकार कुल 2.42 लाख बच्चे बढ़ रहे हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के जीवित रहने के लिए भोजन, हवा, पानी, ऊर्जा, स्थान, घर की आवश्यकता है। इससे प्रकृति पर भारी दबाव पड़ रहा है और यह दबाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए प्रकृति इस तरह की आपदाएं लाती रहती है।

जब इस महामारी के कारणों की बात या चर्चा की जाती है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण तो प्राकृतिक विनाश और असंतुलन ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पांचवी–छठी दशक से दुनिया में आर्थिक विकास का जो पैमाना तय हुआ है, वही विनाश का मुख्य कारण है। दुनियाभर में जिस तरह से पूंजीवादी सोच एवं ताकतों का विकास, विस्तार एवं फैलाव हुआ है, इसके कारण दुनियाभर में प्राकृतिक साधनों, संसाधनों एवं सुविधाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ा है। यही आज प्रकृति के विनाश का कारण बन रही है, जो स्वयं मनुष्य जाति के विनाश का कारण बन रही है। ऐसे में समूची मानवता को सोचने की जरूरत है कि क्या हम अब भी सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी विकास की नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम सही हैं? क्या हमारा विकास का पैमाना सही है? अब जबकि कोविड–19 और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रासंगिकता सिद्ध हो चुकी है, गंभीर विमर्श एवं चिंतन का समय है। ठीक है कि विकास के एक निश्चित चरण के पश्चात जनसंख्या स्वमेव नियंत्रित होने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी होती है, जैसे अभी दुनिया चुका रही है। इसलिए अब जागने, चेतने, सीखने, सबक लेने की सख्त जरूरत है।

निष्कर्ष

कोरोना से जंग लड़ने को लेकर दुनिया के विकसित से विकसित देशों की सरकारें असहाय, निर्बल एवं कमजोर साबित हो रहीं हैं। इस बीमारी, महामारी के कारणों की चर्चा की जाए तो यह साफ है कि यह विनाशकारी महामारी खान–पान, दिनचर्या एवं जीवनशैली की भयानक मूर्खता, लापरवाही एवं अज्ञानता की उपज है। विज्ञान और तकनीक की मदद से मनुष्य जीवन को सफल बनाने की बजाय लोगों ने मनुष्यता को ही जब दांव पर लगा दिया तो इस तरह के खतरे या महामारी का आना लाजिमी है। आज लोगों ने जिस तरह से अपनी जीवनशैली को बदल लिया है, खान–पान, रहन–सहन की आदतों में बदलाव किया है, उसके कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जा रही है, ऐसे में मनुष्य शरीर पर खतरनाक जीवाणुओं एवं विशाणुओं का तेजी से हमला होना स्वाभाविक

है। पर्यावरण, प्रकृति का जिस तरह से विनाश, क्षरण हुआ है और लगातार हो रहा है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, मौसम–जलवायु में जिस तरह से दुनियाभर में बदलाव हुए एवं हो रहे हैं, ऐसे में लोगों का सुरक्षित रहना या बचना कैसे संभव है?

एक कहावत है कि 'दुनिया की हर चीज बाद में उतनी बुरी नहीं निकलती, जितनी कि वह शुरूआत में जितनी बुरी दिखती या जितनी बुरी लगती है,' कोरोना वायरस या कोविड–19 संकट पर भी यही बात लागू होगी या होती है। कोरोना या कोविड–19 संकट जाते–जाते दुनिया के लिए, धरती एवं प्रकृति के लिए और सही अर्थों में मनुष्यता के लिए इतनी सीख और सबक जरूर देकर, छोड़कर जायेगी जिसे सदियों तक लोग याद रखेंगे, जिसे सदियों तक दुनिया याद रखेगी।

कोविड संकट के बाद दुनिया में क्या–क्या बदलाव एवं परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं यह जानना, सोचना एवं समझना जरूरी एवं महत्वपूर्ण है।

- दुनिया में अपवाहों का बाजार हमशा गर्म रहता है। इसके कारणों, बचने के तरीकों या उपाय आदि के बारे में आने वाले वक्त में और भी अपवाहें, भ्रम फैलाने की कोशिश होती रहेंगी, इससे बचने और सावधान रहने की जरूरत है।
- इस समय सोशल डिस्टेंसिंग (वास्तव में यह फिजीकल डिस्टेंसिंग है) को बचने के एकमात्र उपाय के तौर पर पेश किया जा रहा है, और टीका–वैक्सिन लगवाना एक निश्चित उपाय होगा।
- किसी भी देश या दुनिया में जब–जब इस तरह की महामारी, संकट या समस्या आती है, तब अर्थव्यवस्थाएं, रोजगार, उत्पादन, वितरण व्यवस्था आदि पर इसका विपरीत एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
- इस तरह की स्थितियों में कई बार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताओं की खाई गहरी होती जाती है। कई तरह के लोग समाज विघटनकारी कार्यों को अंजाम देते हैं, ऐसे में सरकार एवं विपक्ष दोनों को सावधान रहने की आवश्यकता है।
- लॉकडाउन या तालाबंदी को लेकर सरकार एवं विपक्ष में अक्सर अविश्वास या तनातनी बढ़ती है। नीतियों, निर्णयों को लेकर अमीर–गरीब के बीच भेदभाव भी बढ़ता है। इससे अधिक परेशानी गरीबों, समाज के कमजोर वर्गों को होती है। जैसे इस समय भी देश के करोड़ों गरीब, दिहाड़ी मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसका सामना करना पड़ा है।
- महामारी संकट के बाद दुनिया में मानवतावादी सोच एवं दृष्टिकोण में सुधार आना सुनिश्चित है। लोगों की जीवनशैली में व्यापक बदलाव आना अवश्यंभावी है। लोगों की भोग, उपभोग, लाभ, लोभ की धारणाएं बदलेंगी।
- रोजी–रोटी, रोजगार, काम–धंधे के संकट को लेकर बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलन, वर्ग–संघर्ष की भी आशंका है, जिससे औद्योगिक अशांति एवं समस्याएं पैदा होंगी।
- संकीर्ण राष्ट्रवाद की धारणाएं बढ़ भी सकती हैं और समाप्त भी हो सकती है। कई राष्ट्रों, अन्तरराष्ट्रीय संघों और संस्थाओं के बीच एक नए तरह के संतुलन बन सकते हैं। जैसे WHO को लेकर अमेरिका का विवाद।
- इस समस्या या संकट से उबरने, निकलने को लेकर कार्यशैली में भारी बदलाव होंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिसके साथ तालमेल कर चलना बहुत लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
- कोविड–19 संकट से सबसे कीमती चीज लोगों की वैयक्तिक आजादी या स्वतंत्रता पर भी छाप पड़ सकती है। सरकारें लोगों की निगरानी के लिए इंसानी जिस्मों में चीप लगाकर जासूसी कर सकती हैं। निजी जिंदगी पर निगरानी बढ़ सकती है।
- इस समय दुनियाभर में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता या असमानता चरम पर है। यह विषमता दुनिया के अलग–अलग देशों में अलग–अलग तरह से है। इस संकट के बाद शायद सामाजिक अशांति और बढ़ सकती है।
- इस संकट या महामारी से पूंजीपति, अमीर वर्ग भी प्रभावित होंगे। अब बड़े औद्योगिक घराने पूंजी निवेश को लेकर अत्यधिक सावधानी एवं सर्तकता बरतेंगे, जिसके कारण समाज में बेरोजगारी बढ़ेगी।
- अंततः अब समय आ गया है दुनिया इस महामारी से बचने, निकलने, उबरने के बाद एकजुटता से केवल और केवल मानवता के लिए कार्य करे, इसी में सभी का हित है। यही ईश्वर की, दुनिया की और मानवता की अंतिम इच्छा भी होगी।

संदर्भ

1. 'लॉकडाउन कालखण्ड में रोजगार के दावे–प्रतिदावे' https://youtu.be/It8bHwM_GLM, Jul 09, 2020
2. 'केन्द्र सरकार के विशेश आर्थिक पैकेज पर परिचर्चा' https://youtu.be/MKuToLKyh2I, May 14, 2020
3. 'लॉकडाउन 4.0 और चुनौती पर परिचर्चा' https://youtu.be/Dla6dKelgK8, May 12, 2020
4. 'गिरती–घटती जीडीपी, सिकुड़ता रोजगार और टूटती उम्मीदें' Sep 07, 2020 https://deshtv.in/document/articles/declining-gdp-shrinking-employment-and-falling-expectations/

5. 'कोविड–19 एवं अर्थव्यवस्था : संकट और चुनौतियां' Jun 06, 2020. https://deshtv.in/document/articles/covid-19-and-economy-crisis-and-challenges/
6. 'PSUs की उपेक्षा और निगमीकरण की रास्ते पर देश' May 28, 2020 https://deshtv.in/document/articles/country-on-the-path-of-neglect-and-corporatisation-of-psus/
7. 'कोरोना और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत' Apr. 13, 2020. https://deshtv.in/coronavirus/covid-19-malthus-had-warned-a-hundred-and-two-hundred-years-ago/
8. "पॉलिसी' से नीतियां गायब होना देशहित के साथ धोखाधड़ी' देशबंधु, नई दिल्ली सोमवार 02 नवंबर 2020 https://deshbandhu.co.in/ /admin/epaper/02112020/02112020_DB_NAT_6.pdf.pdf
9. 'निगेटिव जीडीपी से मोदी कैसे बनायेंगे आत्मनिर्भर भारत' देशबंधु, नई दिल्ली गुरूवार 10 सितम्बर 2020 https://deshbandhu.co.in/ /admin/epaper/10092020/10092020_DB_NAT_6.pdf.pdf
10. 'बाजार में मांग पैदा करने में नाकाम आर्थिक पैकेज' देशबंधु, नई दिल्ली सोमवार 12 अगस्त 2020 https://deshbandhu.co.in/ /admin/epaper/12082020/12082020_DB_NAT_6.pdf.pdf
11. 'कोविड–19 : कितनी बदलेगी जिंदगी और दुनिया' दिव्य छत्तीसगढ़, रायपुर (मासिक पत्रिका) जुलाई 2020
12. 'उद्यमिता विकास एवं विकेन्द्रीयकरण के बिना कैसी आत्मनिर्भरता?' देशबंधु, नई दिल्ली सोमवार 22 जून 2020. https://deshbandhu.co.in/ /admin/epaper/22062020/22062020_DB_NAT_6.pdf.pdf